पिछले साल के आंकड़े से आइटीआर में दिख रही गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : इनकम टैक्स विभाग ने 2018-19 में ऑनलाइन दाखिल हुए आइटीआर में 6.6 लाख की गिरावट दिखने को लेकर सोमवार को सफाई पेश की। विभाग ने कहा कि 2018-19 के पहले के असेसमेंट वर्ष के लिए दाखिल हुए आइटीआर के आंकड़े मिले हुए होने के कारण यह गिरावट दिख रही है। टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक 2018-19 में दाखिल हुए रिटर्न की संख्या घटकर 6.68 करोड़ पर आ गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 6.74 करोड़ थी।

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है। मुझे यकीन है ओला इलेक्टिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
— रतन टाटा
पूर्व चेयरमैन, टाटा ग्रुप

सेंसेक्स 38,600.34 ▼ 362.92	निफ्टी 11,598.25 ▼ 114	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 32,720 ▲ ₹75	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 38,130 ▼ ₹70	$ डॉलर ₹ 69.40 ▲ ₹0.18	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 70.70

कारपोरेट हलचल

आइओसी पाइपलाइन की निबंध प्रतियोगिता

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) के नोएडा स्थित पाइपलाइन मुख्यालय ने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने को दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में राजभाषा से संबंधित विषयों पर हिंदी पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। प्रतियोगिता में कुल 109 बच्चों ने हिस्सा लिया।

एनएफएल के लाभ में 40 फीसद की वृद्धि

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने वर्ष 2018-19 में अपने अधिकतम कुल फर्टिलाइजर बिक्री एवं यूरिया उत्पादन के परिणामस्वरूप 463 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। कंपनी के इतिहास में यह सर्वाधिक है। इसके विपरीत शुद्ध लाभ बीते वर्ष के मुकाबले 40 फीसद बढ़कर 298 करोड़ रुपये हो गया। इस वर्ष टर्नओवर में गैर-यूरिया उत्पादों का योगदान वर्ष 2017-18 के 15 फीसद की तुलना में 20 फीसद रहा।

बीएसएफ की एयर विंग की स्वर्ण जयंती

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की एयर विंग के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बल ने दिल्ली के छाबला कैंप में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। बल के महानिदेशक रजनीकांत मिश्र की उपस्थिति में एयर विंग कैंप भी जारी की गई। मिश्र ने एयर विंग के सभी सदस्यों को उनके योगदान व समर्पित सेवाओं के लिए बधाई दी। एयर विंग की स्थापना 1 मई 1969 को 01 क्वीन एयरक्राफ्ट से हुई थी।

वजह ▶ नए कारोबार में मंदी और चुनावी माहौल के चलते दिखी सुस्ती

सेवा क्षेत्र की घटी रफ्तार सात महीने में सबसे सुस्त

चुनाव के बाद कारोबार में तेजी आने की आशा से रोजगार में दिखी बढ़त

नई दिल्ली, प्रेट्र : घरेलू सर्विस सेक्टर की विकास दर अप्रैल में सात महीने के निचले स्तर पर आ गई। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक नए ठेकों में धीमी वृद्धि और चुनाव से कारोबार के बाधित होने के कारण सेवा क्षेत्र की रफ्तार घटी। चुनाव के बाद कारोबार में तेजी आने की आशा से हालांकि रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

निक्केई इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल में गिरकर 51 पर आ गया, जो मार्च में 52 के स्तर पर था। यह सितंबर 2018 से अब तक की सबसे कमजोर रफ्तार है। सेक्टर की धीमी रफ्तार के बावजूद सर्विस पीएमआइ लगातार 11वें महीने 50 से ऊपर है। पीएमआइ की शब्दावली में सूचकांक के 50 से ज्यादा का स्कोर दर्ज करने का मतलब यह है कि सेक्टर में विकास हुआ है। इंडेक्स के 50 से नीचे रहने का मतलब यह है कि सेक्टर में गिरावट आई है।

धीमी रफ्तार की वजह : आइएचएस मार्किट की मुख्य अर्थशास्त्री और इस रिपोर्ट की लेखिका पॉलियाना डी लीमा ने कहा कि भारत के निजी क्षेत्र के विकास में सुस्ती दिख रही है। लेकिन यह सुस्ती मुख्य रूप से चुनाव के कारण कारोबार के बाधित होने की वजह से है। नई सरकार बन जाने के बाद कंपनियों को कारोबार में वापस तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव इस सेक्टर की सुस्ती का अकेला कारण नहीं है। सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों के बीच ऑनलाइन बुकिंग की स्वीकार्यता बढ़ने से भी इंडस्ट्री की ग्रोथ धीमी हुई है।

रोजगार के मोर्चे पर बेहतरी : निकट भविष्य में कारोबार में बढ़ोतरी के अनुमान से सर्विस सेक्टर में अप्रैल में ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। यह सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि उसे रोजगार के मोर्चे पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

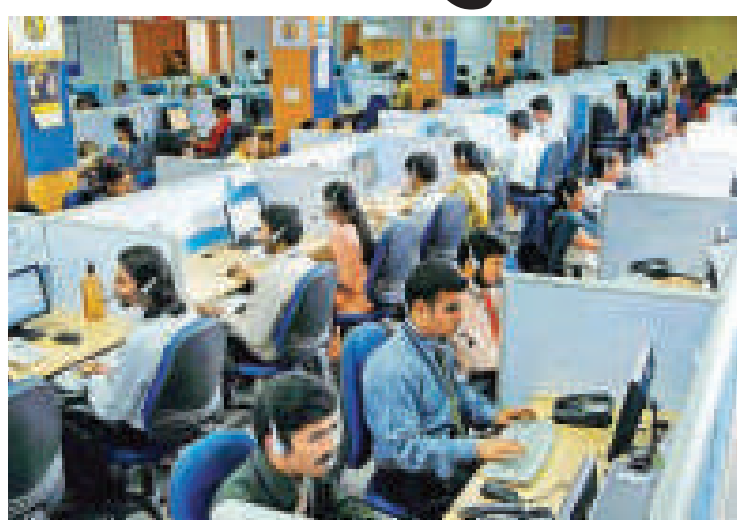

समग्र अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों को मापने वाला निक्केई इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स गिरकर अप्रैल में 51.7 पर आ गया, जो मार्च में 52.7 के स्तर पर था। इससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती का पता चलता है। लीमा के मुताबिक सेवा और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही क्षेत्रों में महंगाई का कोई दबाव नहीं है। इसके साथ ही विकास की रफ्तार भी सुस्त है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य ब्याज दर में और कटौती की गुंजाइश बनी है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक तीन से छह जून तक होगी।

सहायक इकाइयों के बल पर आइसीआइसीआइ बैंक के लाभ में मामूली बढ़त

- एकल आधार पर बैंक के शुद्ध लाभ में थोड़ी गिरावट आई
- सामूहिक लाभ में करीब आधा योगदान टैक्स रिफंड पर मिले ब्याज का रहा

मुंबई, प्रेट्र : सहायक इकाइयों की बदौलत आइसीआइसीआइ बैंक का समेकित शुद्ध लाभ जनवरी-मार्च तिमाही में मामूली रूप से बढ़ा। एक साल पहले की समान अवधि के 1,141 करोड़ रुपये के मुकाबले समेकित शुद्ध लाभ पिछली तिमाही में 1,170 करोड़ रुपये रहा। एकल आधार पर हालांकि बैंक के शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की गई।

निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने कहा कि उसके लाभ में लगभग आधे का योगदान एकल आधार पर हाल के टैक्स रिफंड पर मिले 440 करोड़ रुपये के ब्याज का रहा।

एकल आधार पर बैंक को पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 969 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जो इससे एक साल पहले की समान अवधि में 1,020 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष के लिए बैंक का शुद्ध लाभ 40 फीसद घटकर 3,363 करोड़ रुपये रहा। बैंक को फंसे कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी और गवर्नेंस के मुद्दे पर सीईओ चंदा कोचर की बर्खास्तगी के कारण विपरीत स्थिति से गुजरना पड़ा है। हालांकि बैंक ने कहा कि बुरा समय बीत चुका है।

बैंक के कार्यकारी निदेशक-नामित संदीप बत्रा ने कहा कि हम असेट क्वालिट साइकिल के आखरी चरण में हैं और आने वाले समय में नए फंसे कर्ज में ठहराव आने की उम्मीद है। फंसे कर्ज के लिए किया गया प्रावधान बढ़कर 3.50 फीसद पर पहुंच गया है, लेकिन यह चालू वित्त वर्ष से सामान्य स्तर पर आ जाएगा। फंसे कर्ज में बढ़ोतरी होने से पहले बैंक का प्रावधान 1-1.2 फीसद हुआ करता था।

आलोच्य अवधि में बैंक का नया एनपीए 3,547 करोड़ रुपये का रहा। पूरे वित्त वर्ष के लिए बैंक का नया एनपीए 11,039 करोड़ रुपये का रहा, जो इससे एक साल पहले 28,730 करोड़ रुपये था। पिछली तिमाही में बैंक ने 7,300 करोड़ रुपये के कर्ज को डूबे खाते में दिखाया। इस दौरान बैंक का प्रोविजन कवरेज रेश्यो 60 फीसद से सुधर कर 80 फीसद पर पहुंच गया।

आइएलएंडएफएस में 276 करोड़ का एनपीए

बैंक ने अपने तिमाही नतीजे में आइएलएंडएफएस के 276 करोड़ रुपये के अकाउंट को एनपीए के रूप में दिखाया है। इसके लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आइएलएंडएफएस समूह में बैंक का 545 करोड़ रुपये का नॉन-फंड एक्सपोजर भी है। इसके लिए 468 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एनएसई को-लोकेशन मामले में सेबी के आदेश पर सैट की अंतरिम रोक

- एनएसई में ब्रोकरों के सर्वर लगाने के मामले पर सेबी ने लगाया था जुर्माना
- वर्ष 2015 में कुछ खास ब्रोकरों को विशेष तौर पर सर्वर लगाने का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सिक्युरिटीज अपीलीय प्राधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को सोमवार बड़ी राहत दी है। सैट ने सेबी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें एनएसई के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही शेयर बाजार की गतिविधियों से भी दो साल तक अलग रहने को कहा गया था। यह मामला वर्ष 2015 में एनएसई में ब्रोकरों के लिए सर्वर लगाने (को-लोकेशन) से जुड़ा है। सेबी के पास इस बात की शिकायत पहुंची थी कि वरिष्ठ अधिकारियो की मिलीभगत से कुछ ब्रोकरों के सर्वर इस तरह से लगाए गए हैं कि उन्हें कुछ सूचनाएं दूसरे ब्रोकरों से पहले मिलती हैं। सेबी ने इसकी जांच के बाद हाल ही में एक आदेश दिया था जिसमें सेबी के पूर्व एमडी रवि नारायण, सीईओ चित्रा रामकृष्णा, बिजनेस डवलपमेंट हेड रवि वरानसी समेत सात लोगों और कुछ ब्रोकरों पर आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें शेयर बाजार की गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया था।

सेबी के आदेश को सैट में चुनौती दी गई है। सैट ने फिलहाल सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दायर अनुरोध को स्वीकार करते हुए सेबी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई को तय की गई है।

को-लोकेशन के तहत ब्रोकरों को एनएसई में अपनी केबल लाइन बिछाने व सर्वर लगाने की अनुमति दी जाती है। सेबी ने अपनी जांच में यह पाया था कि कुछ ब्रोकरों को नियमों को ताक पर रख कर सर्वर लगाने की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि उन्हें कुछ सूचनाएं पहले मिल रही हैं। आज के सैट के अंतरिम रोक के बाद उन तीन ब्रोकरों (ओपीसी सिक्यूरिटीज, जीकेएन सिक्यूरिटीज और वे टु वेल्थ) को भी राहत मिली है क्योंकि इन पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ इन्हें दो वर्षों के भी बाजार की गतिविधियों से बाहर भी कर दिया गया था। हालांकि इन पर लगाए गए आर्थिक जुर्माने की 50 फीसद राशि 20 मई तक जमा कराने का आदेश भी सैट ने दिया है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री भारत में, व्यापक वार्ता शुरू

- विल्बर रॉस के साथ 100 कंपनियों के प्रमुखों का दल भी पहुंचा
- भारत को सस्ती दरों पर क्रूड का वादा नहीं कर सकते : रॉस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कारोबार के मुद्दे पर लगातार दूसरे देशों को निशाना बना रहे हैं, वहां के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। सोमवार को उन्होंने भारतीय समकक्ष सुरेश प्रभु से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में भारत की ई-कॉमर्स नीति के मसौदे, डाटा लोकलाइजेशन, स्टील व एल्यूमिनियम के आयात पर अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला उच्च शुल्क तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय कारोबारी पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में जीएसपी का मुद्दा शामिल नहीं था।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों में चिकित्सा उपकरणों, भारत के डाटा प्रोटेक्शन बिल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, डाटा लोकलाइजेशन, वीजा के मुद्दे, अमेरिकी कंपनियों द्वारा एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग परिचालन, बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) तथा एयरलाइन पैसेंजर सुरक्षा डाटा प्रमुखता से शामिल थे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को अमेरिका के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) से बाहर करने के प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत मानता है कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्थानीय कारोबारियों की मांग है कि भारत को यह सुविधा जारी रखने के लिए अमेरिका को मनाया जाए।

वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने लंबित कारोबारी मामलों को सुलझाने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर भी एकमत हैं। रॉस भारत की यात्रा पर अमेरिकी सरकार की ट्रेड विंड्स कार्यक्रम के तहत आए हैं जिसका उद्देश्य 40 देशों में अमेरिकी कारोबार को बढ़ावा देना है। उनकी अगुआई में अमेरिकी कंपनियों का दल भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही स्थानीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करेगा और द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने संबंधी फैसले करेगा।

ई-कॉमर्स का मुद्दा अहम : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के साथ मुलाकात में अमेरिकी अधिकारियों ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर चिंता जाहिर की। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को लगता है कि इससे घरेलू कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा और अमेजन व वालमार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां स्पर्धा में पिछड़ेंगी। दूसरी तरफ, भारत ने अमेरिका द्वारा स्टील व एल्यूमिनियम उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क का मामला उठाया।

अरुण जेटली से भी मुलाकात

रॉस ने सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। इस दौरान ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध के मामले पर भी बात हुई है। इस प्रतिबंध की वजह से भारत अब ईरान से कच्चे तेल की खरीद नहीं कर सकेगा। रॉस से सोमवार को इस बारे में पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत को भरपाई के तौर पर सस्ती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराएगा तो उन्होंने इसका नकारात्मक जवाब दिया। रॉस ने कहा कि अमेरिकी तेल निजी क्षेत्र के हाथ में है और सरकार उनकी कीमत को लेकर फैसला नहीं कर सकती है। इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि तेल की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब समेत दूसरे देशों से बात हो रही है।

सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ी मांग, चांदी सुस्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों के मजबूत रुझान और स्थानीय ज्वेलरों की ओर से भी मांग बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 75 रुपये चढ़कर 32,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से खरीदारी घटाए जाने के कारण चांदी हालांकि 70 रुपये की गिरावट के साथ 38,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

सराफा कारोबारियों ने कहा कि स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग बढ़ने के अलावा विदेशी बाजारों में रुझान मजबूत रहने से भी पीली धातु की कीमत बढ़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा करने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का आकर्षण बढ़ गया। ट्रंप ने रविवार को कहा कि चीन के साथ उसकी व्यापार वार्ता की प्रगति काफी धीमी है। इसलिए अमेरिका इस सप्ताह के आखिर से चीन से होने वाले 200 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क को वर्तमान 10 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद कर देगा। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध के और तीखा हो जाने की आशंका बढ़ गई। न्यूयॉर्क में सोने में 1,282.60 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 14.91 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 75 रुपये चढ़कर 32,720 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 32,550 रुपये प्रति 10 ग्राम का हो गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी हालांकि 26,400 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही।

चांदी हाजिर 70 रुपये की गिरावट के साथ 38,130 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि वीकली डिलीवरी 313 रुपये चढ़कर 37,290 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई।

आरबीआइ व बैंकों से वित्त आयोग करेगा मुलाकात

- एनके सिंह के नेतृत्व में 8-9 मई को मुंबई में आरबीआइ और प्रमुख बैंकों संग होगी बैठक
- इस पर भी होगी बात कि अगले पांच वर्षों में सरकार को कितना लाभांश दे सकता है बैंक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर 15वां वित्त आयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के साथ इसी सप्ताह चर्चा करेगा। आयोग आरबीआइ से यह भी जानना चाहेगा कि अगले पांच साल में केंद्रीय बैंक सरकार को लगभग कितनी राशि लाभांश व अतिरिक्त पूंजी के मद में ट्रांसफर कर सकता है।

आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, इसके सदस्य तथा कई वरिष्ठ अधिकारी इस सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मुंबई में होंगे। इस दौरान वे आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास तथा अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की उधारी की लागत को लेकर आरबीआइ के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाएगा। उधारी लागत बाजार से ही तय हो, यह सुनिश्चित करने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही केंद्र और राज्यों के कर्ज को कम करने के संबंध में रोडमैप, बैंकों को फिर से पूंजी मुहैया कराने की जरूरत और सरकार की उधारी पर उसके प्रभाव समेत सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

15वें वित्त आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार आरबीआइ के पास उपलब्ध सरप्लस कैपिटल को सरकार को ट्रांसफर करने के बारे में बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आयोग ने आरबीआइ से इस बात का अनुमान भी लगाने को कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि (अप्रैल 2020 से मार्च 2025) केंद्रीय बैंक के पास लाभांश और सरप्लस के रूप में केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध होगी।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ वित्त आयोग की बैठक में एसबीआइ, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित सरकारी बैंक तथा आइसीआइसीआइ बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे निजी बैंक शामिल होंगे।

अमेरिका-चीन तनाव के गहराने की आशंका से बाजार लुढ़के

मुंबई, प्रेट्र : अमेरिका और चीन के बीच तनाव गहराने से सोमवार को देश के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 362.92 अंकों की गिरावट के साथ 38,600.34 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 114 अंकों की गिरावट के साथ 11,598.25 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चीन के 200 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क को वर्तमान 10 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने की चेतावनी दे दी। इससे दोनों देशों की व्यापार वार्ता के पटरी से उतरने की आशंका गहरा गई।

सेंसेक्स में यस बैंक में सर्वाधिक 5.30 फीसद गिरावट दर्ज की गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने बैंक की लंबी अवधि की रेटिंग को घटा दिया है और इसके आउटलुक को नकारात्मक कर दिया है। गिरावट वाले अन्य ब्लूचिप शेयरों में टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक में 4.49 फीसद तक की गिरावट रही। दूसरी ओर सेंसेक्स में आइटीसी में सर्वाधिक 1.12 फीसद तेजी रही। अन्य शेयरों में टाटा केमिकल्स में 8.59 फीसद उछाल दर्ज किया गया। कंपनी के समेकित शुद्ध लाभ में शुक्रवार को 26.46 फीसद बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु सेक्टर में सर्वाधिक 2.82 फीसद गिरावट रही। धातु सेक्टर भी 2.07 फीसद लुढ़का। दूसरी ओर एकमात्र सेक्टर तेल एवं गैस में 0.19 फीसद तेजी रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.79 फीसद और स्मॉलकैप में 0.85 फीसद गिरावट रही।

शेयरखान के एडवायजरी प्रमुख हेमांग जानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन के आयात पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा से बाजार में गिरावट आई है। ट्रंप ने रविवार को एक ट्वीट में शुक्रवार से चीन के आयात पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है।

दुनियाभर के बाजार गिरे

चीन के आयात पर शुल्क बढ़ाने की अमेरिका की चेतावनी से पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट देखी गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 5.58 फीसद गिरावट रही। हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाजारों में भी गिरावट रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुझान देखा गया। अमेरिका में डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज के फ्यूचर कांट्रैक्ट में दो फीसद और एसएंडपी के फ्यूचर कांट्रैक्ट में 1.9 फीसद गिरावट देखी गई।

तल्खी

टेस्ला के इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने की योजना पर बफेट ने कसा तंज, मस्क ने ट्विटर पर इंश्योरेंस कारोबार के दिग्गज को दिया जवाब

इंश्योरेंस पर मस्क-बफेट में नोंकझोंक

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वारेन बफेट द्वारा ऑटो दिग्गज टेस्ला के प्रस्तावित इंश्योरेंस कारोबार पर की गई टिप्पणी एलन मस्क को नागवार गुजरी है। पिछले सप्ताह बर्कशायर हैथवे की सालाना बैठक से पहले निवेशकों के साथ सवाल-जवाब के क्रम में बफेट ने कहा था कि इंश्योरेंस कारोबार टेस्ला के बस की बात नहीं है। उसके बाद बफेट और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच ट्विटर पर नोंकझोंक शुरू हो गई।

निवेशकों के सवाल के जवाब में इंश्योरेंस कारोबार के दिग्गज बफेट ने कहा था, 'ऑटो बिजनेस में सफलता से उत्साहित होकर इंश्योरेंस के कारोबार में उतरना करीब-करीब वैसा ही है इंश्योरेंस के कारोबार की सफलता से उत्साहित होकर ऑटो बिजनेस शुरू करना। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस का कारोबार टेस्ला के बस की बात नहीं है।'

गौरतलब है कि टेस्ला के वित्तीय नतीजों की घोषणा करते हुए पिछले महीने सीईओ एलन मस्क ने इंश्योरेंस उत्पाद लांच करने के मंसूबे जाहिर किए थे। उनके मुताबिक टेस्ला का यह प्रोडक्ट इसी महीने लांच होना है। एक टीवी चैनल के मुताबिक बफेट ने कहा कि मैं किसी भी ऑटो कंपनी के इंश्योरेंस कारोबार में उतरने के खिलाफ हूं। उसके बाद पिछले सप्ताह रविवार को एलन मस्क ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक लिंक भेजा जिसमें कहा गया था कि वे टेस्ला मॉडल-3 खरीदें, जो होंडा अकॉर्ड से सस्ती है। दूसरे ट्वीट में मस्क ने कहा कि टेस्ला में होंडा अकॉर्ड के मुकाबले और भी हजार फायदे हैं। तीसरे ट्वीट में मस्क ने कहा कि यह वारेन बफेट का ही कथन है।

बफेट पिछले कुछ समय से मस्क की आलोचना करते रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि मस्क को अपने ट्वीट्स के माध्यम से सनसनी पैदा करने के लिए जाना जाता है और उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश है।

ट्रेड वार से दुनियाभर को नुकसान

न्यूयॉर्क : वारेन बफेट ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और चीन में ट्रेड वार से दुनियाभर को नुकसान होगा। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने ऐसी कई अमेरिकी कंपनियों में बड़ा निवेश किया हुआ है, जो चीन में कारोबार कर रही हैं। इनमें दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एपल इंक भी शामिल है, जिसमें बर्कशायर हैथवे ने 50 अरब डॉलर (लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता वाला ट्रेड वार हर उस कंपनी के लिए नुकसानदेह होगा, जिसमें बर्कशायर हैथवे का निवेश है।

फॉक्सवैगन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी की दिग्गज ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन एजी पर किसी भी गंभीर कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया हुआ है। कंपनी पर आरोप है उसने अपनी डीजल कारों में ऐसे गुप्त उपकरण लगाए, जो वाहनों से प्रदूषण उत्सर्जन को तय सीमा के अंदर दिखाते थे।

जस्टिस एसए बोवड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फॉक्सवैगन के जुर्माने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। एनजीटी ने इस वर्ष सात मार्च को कंपनी पर 500 करोड़ रुपये जुर्माना लगाते हुए दो महीनों के भीतर रकम जमा कराने का आदेश दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में प्राधिकरण ने कहा था कि कंपनी द्वारा अपने वाहनों में ऐसे गुप्त उपकरण लगाने से भारत में पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

गौरतलब है कि फॉक्सवैगन पर दुनियाभर में इसी आरोप के तहत अलग-अलग मामले चल रहे हैं। अमेरिका समेत कुछ बाजारों में कंपनी ने अरबों रुपये का जुर्माना भरकर स्थानीय एजेंसियों से सुलह कर ली है।

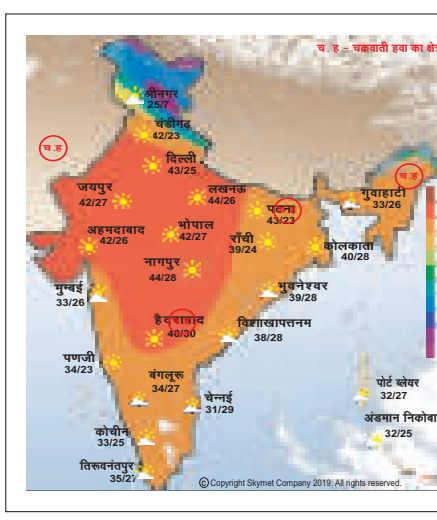

मौसम विशेष

दिल्ली और राजस्थान में धुलभरी मध्यम गति की गर्म हवाएं चलेंगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मौसम शुष्क तथा काफी गर्म रहेगी। आसमान साफ रहेगा। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के मैदानी भागों में मौसम शुष्क व काफी गर्म रहेगा। पर्वतीय भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/27/व	अहमदाबाद	39/22/आंबा
कोलकाता	41/29/रसा	बड़ौदा	39/23/आंबा
चेन्नई	37/29/व	नागपुर	45/28/आंबा
हैदराबाद	41/31/रसा	इन्दौर	41/26/रसा
बंगलूरू	33/26/रसा	रांची	45/25/रसा
त्रिवेन्द्रम	34/26/आंबा	पटना	43/27/रसा
गुवाहाटी	33/26/रसा	जमशेदपुर	44/24/व
गंगटोक	16/07/व	पुणे	32/22/आंबा